THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI MUTHYAL RAO): (a) and (b). The details are being collected and will be laid on the table of the House in due course.

(c) Under the present law, courts have the discretion to award sentences depending upon the circumstances of each case.

(d) The question of amending the Untouchability (Offence) Act is under consideration in consultation with the State Governments.

12.12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

BURNING OF AL-AQSA MOSQUE IN JERUSALEM

MR. SPEAKER: We pass on to Calling Attention. There are a number of persons who could not be included in this list. I will allow one or two of them. *(Interruption)*

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): Sir, only names balloted should be allowed. *(Interruption)*

MR. SPEAKER: Shri Mukerjee.

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta North East): Sir, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:

"The reported burning of Al-Aqsa Mosque in Jerusalem and its tremendous repercussions in India."

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH): Mr. Speaker, Sir, according to information received from our Embassy in Amman the famous Al-Aqsa Mosque was set on fire around 7 a.m. on Thursday, 21st August. 1969. The fire lasted about three hours and damaged the south-eastern wing of the mosque. The central portion including the main dome has fortunately remained unharmed.

The Government and the people of India are deeply shocked and pained at this sacrilege of the holy shrine. I am sure the House will join me in expressing our strong condemnation of this act of descration.

The continued occupation of Jerusalem by Israel in defiance of resolutions of the United Nations is a matter of grave concern. The shocking incident makes it imperative that the Security Council's Resolutions on Jerusalem should be implemented without delay. In this context, Israel cannot be absolved of responsibility for this outrage.

Our Missions are already in touch with Governments of some friendly countries to see what further action needs to be taken.

SHRI H. N. MUKERJEE: In this matter India has a special responsibility not only because we have the third largest Muslim population in the world but we have already taken a stand regarding the use of Israel as the tool of western imperialism and as a weapon powerfully poised against Arab freedom. I am glad the Minister, in diplomatic language, appears to agree with the firm Arab conviction that Israel was responsible for the dastardly incendiarism and that the Israeli attempt to foist blame on an Australian has been considered by the Arabs to be a hideous and dishonest way of hiding the guilt of Israel. In view of this I would like to know what initiative Government is going to take in good time, because India is a country of which much is expected in this kind of a problem, and therefore, I want to know the particular type of initiative they are going to take to ensure that the status of Jerusalem and the holy places in that region which were brought blazingly into the agenda of the day. is solved properly? The Minister has said that Israle has defied interna-

tional agreements, Israel has defied Security Council Resolutions and is now guilty of this terrible crime. Therefore, it is necessary for Government to take the initiative to do something through the Security Council for the return of Jerusalem to the Arabs and at least for the immediate internationalisation of the region. The United Nations is going to meet on the 16th of September or thereabouts, and, therefore, it is more than time that India not only consults in a pressing way our friends in the international body but takes some initiative in this regard to punish Israeli intransigence of this dastardly sort. That initiative should be taken by our Government. I would like to know what Government have to say in this regard.

SHRI DINESH SINGH: The hon. Member is aware of the steps that we have taken in the United Nations and how we have been associated with the resolutions that have been passed by the United Nations regarding Jerusalem.

So far as this particular incident is concerned, this becomes all the more relevant in the context of the UN resolutions, because the mosque lies in the area of Jerusalem occupied by Israel, and as the House is aware, we are doing our best to persuade the international opinion which has already been expressed by the resolution of the Security Council to move in the matter and to find some peaceful solution to the problem of West Asia. This is linked very much with it because if we can find a solution then one could think in terms of the return of this territory which is occupied by Israel by force. In this particular regard, Jordan has already moved the UN to call a meeting of the Security Council. The Arab Foreign Ministers are meeting in Cairo, and we are closely in touch with them to see what international action is called for.

श्री इसहाक साम्भली (अमरोहा) : सदर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि इज़राइल की इस ज़्यादती और जुल्म के बाद जो पूरे वर्ल्ड के इंसाफ पसन्द लोगों में एक आग लग गयी है और हर तरफ इस पर सख्त तकलीफ का इज़हार किया जा रहा है. हमारे यहां भी जा बजा इस सिलसिले में जलूस, डेमान्स्ट्रेशन ये सब कुछ हो रहे है, इज़राइल का यह काला कारनामा केवल इन्सानियत पर जुल्म नहीं है ही, इसके अलावा इतना ही नहीं है इजरायल का यह काला कारनामा युनाइटेड नेशन्स के चार्टर के भी खिलाफ है। आप को मालूम है कि युनाइटेड नेशन्स ने अपने चार्टर में यह जिम्मेदारी ली है कि हर मुल्क के अन्दर हिस्टारिकल और रिलिजस मकामात की इज्जत, उस की हिफाजत, उस का आदर करना यह उस मुल्क की जिम्मेदारी होगी। इज़राइल ने ऐसी मस्जिद को जिस की बहुत बड़ी तारीखी अहमियत है. जो कि वर्ल्ड भर के मुसलमानों के लिये बहुत ही मुकद्दस जगह है उसकी जो बेहुरमती की है, उस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, जरूरत इस बात की है कि इस सिलसिले में हमारी सरकार उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले। हमारा मुल्क जो युनाइटेड नेशन्स का एक इम्पॉर्टेन्ट मेम्बर है, उसके लिये जरूरी है कि वह युनाइटेड नेशन्स के सेक्रेटरी जनरल की तवज्जह दिलाये कि युनाइटेड नेशन्स के चार्टर की जो इन्सलट की गई है। इस बारे में न केवल इज़राइल का जवाब भी तलब किया जाये बल्कि उसके खिलाफ जो भी मुनासिब कदम हो इस जुल्म को खत्म कराने के लिये और चार्टर की इनसल्ट के बारे में, वह कदम उठाया जाये। इसके लिये सरकार क्या कर रही है ?

[شری اسحاق سمبھلی (امروھا)
صدر صاحب ، میں جاننا چاھتا ھوں
کہ عزرائیل کی اس زیادتی اور ظلم
کے بعد جو پورے ورلڈ کے انصاف
پسند لوگوں میں ایک آگ لگ
گئی ھے اور ھر طرف اس پر سخت

[شری اسحاق سمبھلی]

تکلیف کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ ہمارے یہاں بھی جابجا اس سلسلے میں جلوس و ڈمانسٹریشن، یہ سب کچھ ہو رہے ہیں، عزرائیل کا یہ کالا کارنامہ کیول انسانیت پر ظلم تو ہے ہی، اس کے علاوہ اتنا ہی نہیں ہے، عزرائیل کا یہ کالا کارنامہ یونائیٹڈ چارٹر کے بھی خلاف ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز نے اپنے چارٹر میں یہ ذمہ داری لی ہے کہ ہر ملک کے اندر ہسٹوریکل اور ریلیجس مقامات کی عزت، اسکی حفاظت، اس کا آدر کرنا یہ اس ملک کی ذمہ داری ہوگی - عزرائیل کے ایسی مسجد کو جسکی بہت بڑی تاریخی حیثیت ہے جو کہ ورلڈ بھر کے مسلمانوں کے لئے بہت ہی مقدس جگہ ہے، اسکی جو بے حرمتی کی ہے، اس کو ڈسٹروئے کرنے کی کوشش کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سلسلے میں ہماری سرکار اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمارا ملک جو یونائیٹڈ نیشنز کا ایک امپورٹینٹ ممبر ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل کی توجہ دلائے کہ یونائیٹڈ نیشنز کے چارٹر کی جو انسلٹ کی گئی ہے اس کے بارے میں نہ کیول عزرائیل کا جواب طلب کیا جائے بلکہ اس کے خلاف جو بھی مناسب قدم ہو اس ظلم کو ختم کرنے کے لئے اور چارٹر کی انسلٹ کے بارے میں وہ قدم اٹھایا جائے- اس کے لئے سرکار کیا کر رہی ہے-

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि मैंने अभी कहा, अध्यक्ष महोदय इस वक्त तो मांग हो रही है कि इस मसले पर सुरक्षा परिषद में बहस हो। बहस के बीच में जिन बातों का माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है उन बातों पर जो चर्चा उठेगी जरूर उन पर ध्यान दिया जायेगा, और उन पर भारत क्या करेगा। यह तो उसी वक्त, जब मामला आये, तभी हम बता सकते हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि इस समय हम सुरक्षा परिषद के मेम्बर नहीं हैं। लेकिन जो कुछ भी इसमें एक संयुक्त राष्ट्र के मेम्बर के नाते हम कर सकते है, उस के लिये हम इस वक्त चेष्टापूर्ण हैं कि हम पता लगाये, समझे कि क्या चीज की जा सकती है।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : अध्यक्ष महोदय, इस मसले का एक पहलू यह है जिसका कि जिक्र हुआ है कि यह अल-अक्सा मस्जिद संसार के करीब 50 करोड़ लोगों का पवित्र तीर्थस्थान है और हमारे अपने देश की जनसंख्या का एक अच्छा खासा हिस्सा इसको अपना तीर्थ स्थान मानता है और उन के दिलों में इस के लिए बड़ी इज्जत है। साथ ही इसका एक दूसरा पहलू यह है कि संसार के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों में यरूशलम का एक विशेष स्थान है और उसमें अल-अक्सा मस्जिद का एक बहुत ही अहम हैसियत रखती है। यह मस्जिद 1400 वर्ष पुरानी है और जैसे बुद्ध, ईसा, राम, कृष्ण आदि महामानव हुए हैं उन्हीं महामानवों की श्रेणी में यह मुहम्मद साहब भी आते हैं। यह अल अक्सा मस्जिद अपने जमाने की यादगारी और तवारीख़ी मस्जिद है। ऐसी परिस्थिति में जिस बात की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा वह यह है कि इजरायल की सरकार ने इस जुर्म को कबूल

करने की हिम्मत तो नहीं की मगर उस ने एक नया संसार व्यापी विवाद खड़ा करने का प्रयास किया है और ईसाई जगत को इस कांड में समेटने का प्रयास किया है कि जैसे इजरायल ने कहा कि एक आस्ट्रेलियाई युवक रोहन ने यह आग लगाने का काम किया है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार इस झूठ के खिलाफ कोई क़दम उठा रही है, राष्ट्रसंघ के स्तर पर या सरकारी स्तर पर उठा रही है ?

दूसरे सुरक्षा परिषद् की बैठक बुलाई जाय और यह बैठक इस बात के लिए बुलवाई जाय ताकि अन्तर्राष्ट्रीय मंच की ओर से इस की जांच हो क्योंकि इजरायल सरकार की जो स्थिति है उस में वह इस की ठीक जांच नहीं कर सकती है और इस के लिए उस पर विश्वास नहीं हो सकता है । ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि उस की जांच अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की ओर से हो, संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से हो, उसकी बैठक तुरन्त बुलाई जाय । मै जानना चाहता हुं कि इसमें भारत सरकार ने पहल की है कि नहीं और उस ने इस अन्तर्राष्ट्रीयसंगठन की बैठक के लिए और राष्ट्र संघ की ओर से इस की जांच करने की मांग की है या नहीं ?

श्री दिनेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं ने अभी काफ़ी विस्तार से बताया कि क्या इस में अन्तर्राष्ट्रीय रंग पर हो रहा है । जोर्डन ने एक बैठक की मांग की है । उस में जिन देशों की जरूरतपड़ेगी सहयोग की उन में से भारत भी एक देश है और वह इस के लिए पूरी तरह से तैयार है ।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं ने पूछा है कि आप ने मांग की है या नहीं की है ?

श्री दिनेश सिंह : जाहिर है कि नहीं की है क्योंकि अगर की होती तो मैं कह देता उस में छिपाने की तो कोई बात है नहीं । सवाल तो यह है कि एक देश ने मांग की है, दस देशों की एक साथ मांग करने की आवश्यकता नहीं है । इस वक्त अरब फौरेन मिनिस्ट मिल रहे हैं । आगे क्या क़दम उठाया जायगा सब बातचीत करके तय करेंगे खाली एक जोश में दौड़ जाने से कोई आगे नहीं पहुंचता है । सब को इस मामले में मिल कर काम करना है ।

श्री भोगेन्द्र झा : हमारे मांग करने पर इस में क्या कोई रोक है ?

SHRI P. M. SAYEED (Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands): The sacrilege of the Al-Aqsa mosque in Jerusalem was one of the plots of Israel, because this attempt was repeated many a time. May I draw your attention to an article written in Al-Anwar, (Beirut); dated the 23rd August, 1969: which reads thus:

> "In 1929, a Zionist leader claimed that the Al-Aqsa mosque was situated in the place of Solomon Temple. So, the mosque was their property. In the early thirties, the British Zionist Minister, Lord Miliohit announced that the day of reconstruction of Solomon Temple was near and he will pass the rest of his life for the same purpose.'.

This shows the concrete plot made by the imperialists through Israel. This is a very serious question to which India must pay its utmost attention, because India is having the third largest Muslim population. I have got the picture of the *Al-Aqsa* mosque after it has been burnt. I find from the picture some Zionist girls standing in front of the mosque and reciting some verses. A religious leader is telling them that they are before the most sacred place of the Zionists, and in the nearest future this mosque will be vanished to build the Solomon Temple in its place. Even the hon. Minister has admitted in his statement that the fire lasted for three try to see through diplomatic channels that we, the Tamils in India, are

[Shri P. M. Sayeet]

there, the first thing that they did was to demolish some of the compounds of the mosque. That itself shows that they wanted to demolish the entire mosque and build a Solomon temple there.

In this context, I want a categorical answer from the hon. Minister whether the Government of India approached the Secretary-General U Thant in this matter, and if so, what was his reaction? Secondly, would Government approach friendly countries to mobilise opinion against Israel for this naked nefarious act? Thirdly, since this incident involves a well-knit plot, and even if Israel is going to set up any inquiry commission the truth will not come out, what is required is an international commission under UN auspices to find out the actual facts. Would Government take steps towards this end?

SHRI DINESH SINGH: I entirely agree that this act is not only a condemnable act but an act against the whole humanity as such because it affects certain values, the history of the building, its grandeur, the religious feelings it evokes. All these are values we all cherish in different parts of the world. It is not only a question of Muslim sentiment; it is a question of the sentiments of all peoples. That is the point we are trying to emphasise in this matter.

As for reference to the Secretary-General, it is no longer necessary when the Security Council has been moved in the matter. Regarding approaching friendly countries, I have already said in my statement what we are doing. The rest of the points he made is really arguing the case. This will be done when it comes before the Security Council.

श्री स॰मो॰बनर्जी (कानपुर) : सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष महोदय, उस इसरायल सरकार की मजम्मत करता हूं जिसने कि यह हालत पैदा किये है कि यरुशलम की वह मुकद्दस और तवारीखी मस्जिद जहां पर कि पिछले एक हजार साल से ज्यादा से करोड़ों लोग जा कर सिजदा करते हैं, जहां पर करोड़हा करोड़हा लोगों ने सिर झुकाया होगा उस इबादतगाह में आग लग गई, अल अक्सा मस्जिद जल गई और हमें खबर तक न हुई । मैं तो उनको दोषी ठहराता हूं । हमारी नजर में वह जो काम उन्होंने किया है, अल अक्सा मस्जिद को जला कर, वह तमाम अरब वर्ल्ड को अटैक करने का काम उन्होंने किया है ।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो अभी कहा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया इस कंडैम करती है और उन्होंने भी इसको कंडैम किया और हालत के पेशनजर जो कार्यवाही जरूरी थी वह उन्होंने की है यह भी उन्होंने हमें बतलाया है लेकिन आज हमारे इस देश के करोड़ों मुसलमान भारत सरकार से यह आशा करते हैं कि जब हमारा काफी असर है युनाइटेड नेशन्स में, सिक्योरिटी कौंसिल में हम मेम्बर भले ही न हों लेकिन सिक्योरिटी कौंसिल के अलावा वह जो युनाइटेड नेशन्स का हियूमन राइट्स कमिशन है उसमें भी इस मामले को ले जा सकते हैं । यह सवाल केवल मुसलमानों की इबादतगाह के जलाने का ही नहीं समझना चाहिए बल्कि जो सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं जो विश्वास रखते हैं कि आज इस देश में हिन्दू, मुसलमान सिक्ख और ईसाई भाई भाई हैं, जो विश्वास करते हैं कि धर्म का झगड़ा नहीं है, चोटी और दाढ़ी की लड़ाई नहीं है बल्कि यह रोजी और रोटी की लड़ाई है । वह विश्वास करते हैं कि मंदिर, मस्जिद गिरजा आदि धर्मस्थानों में पूजास्थानों में जाकर हम एक हो सकते हैं । इंसानियत का तकाजा है कि सब एक हों और मैं इसका सहारा लेकर पूछना चाहता हूं कि केवल करोड़ों मुसलमानों की ही नहीं बल्कि और लोग भी जोकि फिरकापरस्त नहीं हैं, जो साम्प्रदायिकता में विश्वास नहीं करते हैं,

सैकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, उनकी सही तर्जुमानी करने के लिए क्या आज हमारी सरकार हियुमन राइट्स कमिशन के सामने इस मामले को भेजेगी, नहीं भेज सकती है तो उसके लिए क्या कारण हैं वह कारण हमें मालूम होना चाहिए ताकि हम लोग कह सकें ।

दूसरी बात यह है कि मैं मंत्री महोदय की मार्फत प्रधान मंत्री से कहना चाहता हूं कि जब भी यह मसला यूनाइटेड नेशन्स में आये या सिक्योरिटी कौंसिल में आयें तो वह वहां पर सब की एक राय करने के लिये कोशिश करें और जो भी देश उनके मेम्बर हैं उनको चिट्ठियां लिखें और कहे कि सख्त तरीके से इस मामले की मज़म्मत की जाय । साथ ही इस जगह इजराइल के हाथों से निकाल कर किसी इंटरनेशनल एजेंसी के पास रखा जाय ।

श्री दिनेश सिंह : पहला सवाल जो माननीय सदस्य ने हियूमन राइट्स कमिशन बारे में किया उसको मैं समझा नहीं । क्या वह चाहते हैं कि सिक्योरिटी कौंसिल से उसको हटा कर हियूमन् राइटस् कमिशन को भेज दिया जाये ?

श्री स० मो० बनर्जी : दोनों जगह रह सकता है ।

श्री दिनेश सिंह : दोनों जगह ही नहीं इस जगहों पर बातें हो सकती हैं । इसकी कमी नहीं है । लेकिन सिक्योरिटी कौंसिल में ज्यादा अहम तरीके से इस मामले को लिया जा सकता है । इस लिये माननीय सदस्य इस मसले को हियूमन राइट्स कमिशन से मिलायें नहीं । इसमें कई मामले आते हैं । जैसा मैंने कहा कि यह आकुपाइड टेरीटरी है और इजराइल वहां था इसलिये उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और उस को उन्होंने पूरे तरीके से नहीं निभाया । यह सब मसले सिक्योरिटी कौंसिल में एक बड़े तरीके से उठेंगे । उस के बाद जहां जहां जरूरत हो इस पर बहस की, वह हो सकती है । लेकिन हम तो इस का हल जल्दी निकालना चाहते हैं, और वह हल सिक्योरिटी कौंसिल में ज्यादा आसानी से निकल सकता है । अगर इस के आगे कहीं यह जाता है या ले जाना पड़ता है, तो आगे जो बातचीत हो रही है उस के हिसाब से जहां मुनासिब होगा उन फोरम्स पर बहस हो सकती है ।

दूसरा सुझाव माननीय सदस्य ने रक्खा था कि इस बारे में प्रधान मंत्री कुछ और देशों को लिखें । जब यह सवाल सुरक्षा परिषद् में आयेगा तब जो भी जरूरत होगी उस में हम मदद करेंगे । आज इस के सिलसिले में जो काम करना है उस के लिये हम खुद ही बात कर रहे हैं अरब देशों से और औरों से कि क्या क्या करना है । अरब देशों क भी मीटिंग हो रही है । मीटिंग का अभी कोई फैसला नहीं निकला है । हम उन से काफी समपर्क में हैं । जिन बातों की जरूरत होगी, जिन को हम कर सकते हैं, उन से हम पीछे नहीं हटेंगे ।

12.33 hrs.

POINT OF ORDER

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं । प्रधान मंत्री श्री जगजीवन राम और फखरुद्दीन साहब ने स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ के ऊपर यह आरोप लगाया था कि इस राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस प्रेजिडेंट से मिल कर एक कांस्पिरेंसी की है गवर्नमेंट को टापल करने के लिये । (**व्यवधान**) कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह फैसला किया है कि यह चार्जेज गलत हैं । (**व्यवधान**) मैं आप के द्वारा मांग करता हूं कि यह सरकार, उस की प्राइम मिनिस्टर माफी मांगे, पब्लिक अपालोजी दें क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह फैसला किया है कि यह चार्जेज गलत हैं । यह मेरी पार्टी की डिसरिप्यूट के लिये है और उस को बदनाम